संपादकीय

आयात व परियोजना में देरी को टालें

ऐसे वक्त में जब दुनिया में युद्ध लगातार हाईटेक होते जा रहे हैं, और चीन व पाकिस्तान की तरफ से निरंतर प्रतिरक्षा संबंधी नई-नई चुनौतियां मिल रही हैं, हमें अपनी रक्षा तैयारियों में किसी भी तरह की ढील नहीं देनी चाहिए। इसके लिये उन्नत तकनीक वाले हथियारों से सेना को तुरंत लैस करने तथा रक्षा परियोजनाओं के लक्ष्य भी समय से पूरा करने की सख्त जरूरत है। रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति द्वारा बीते मंगलवार को लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में ऐसी तमाम चिंताओं का जिक्र किया गया है। समिति भारतीय सेना के सामने विद्यमान चुनौतियों का विस्तृत उल्लेख करती है। रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है कि वायु सेना को आपूर्ति के लिये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किये जा रहे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राप्ट यानी एलसीए की सप्लाई में देरी हुई है। वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए सरकार को आगाह किया गया है कि बिना अधिक समय गंवाए पांचवीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। दरअसल, ये आधुनिक विमान थल सेना को हवाई सहायता, नजदीकी युद्ध और जमीनी हमलों से देश को सुरक्षित करने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहां उल्लेखनीय है कि एक अन्य संसदीय पैनल ने भी इस समस्या की ओर दो साल पहले ध्यान दिलाया था। पैनल का कहना था कि हितधारकों के बीच समन्वय की कमी और निगरानी एजेंसियों के द्वारा समय सीमा निर्धारित करने के लिये ढुलमुल दृष्टिकोण के चलते तेजस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। यह स्वीकार्य नहीं है कि प्रमुख लड़ाकू जेट के डिजाइन, सिस्टम और हथियारों को उन्नत बनाने के मुद्दे में अनावश्यक विलंब हो। नि:संदेह, ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना में विलंब से जहां लागत बढ़ जाती है, वहीं समय की चुनौती का मुकाबला करना कठिन हो जाता है। ऐसे में नियामक तंत्र को सजग, सचेत और समय पर आपूर्ति के लिये क्रियाशील रहने की जरूरत है।

इसमें दो राय नहीं कि चारों दिशाओं से देश की घेराबंदी करने वाले चीन और हमेशा भारत विरोधी कृत्यों में लिप्त रहने वाले पाकिस्तान की चुनौती को देखते हुए हमें हर समय उच्च स्तर की रक्षा तैयारियां बनाये रखने की आवश्यकता है। यही वजह है कि संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि चीन व पाकिस्तान की चुनौती को देखते हुए सेना के पूंजीगत बजट को अविलंब बढ़ाया जाये। सीमा पर लगातार उपस्थित खतरे के चलते ऐसा करना अपरिहार्य ही है। निस्संदेह, हर तरह से सेना की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। रक्षा संसाधनों का आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण भी समय की मांग है। सरकार कोशिश करे कि इस कार्य में वित्तीय संसाधनों की कमी न हो। वहीं यह भी जरूरी है कि रक्षा जरूरतों के स्वदेशीकरण व आधुनिकीकरण के लिये आवंटित धन का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। साथ ही यह भी कि इनका लाभ सेना को समयबद्ध ढंग से मिले। निस्संदेह, सेना का लगातार बढ़ता आयात बिल एक अन्य बड़ी चुनौती है। ऐसे में आयात कम करना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। आयात तब कम होंगे जब देश सैन्य उपकरणों व आधुनिक हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसे में हमें न केवल सेना की जरूरतों को देखते हुए उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि देश में तैयार सैन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। निस्संदेह, यदि देश में स्वदेशीकरण के अभियान को गति दी जाती है तो न केवल हम अपनी जरूरतें देश में ही पूरा कर सकेंगे, बल्कि निर्यात के जरिये दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी हासिल करके अर्थव्यवस्था को संबल दे सकते हैं। विदेशी स्रोतों पर हथियारों की निर्भरता कम करने से हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में कामयाब होंगे। लेकिन जरूरी है कि हम विमान, हथियार व अन्य उपयोगी उपकरणों की आपूर्ति समय सीमा के भीतर करें। इस कार्य में सक्षम व योग्य भारतीय निजी उत्पादकों को भी मौका दिया जाना चाहिए। यह जानते हुए कि 21वीं सदी के युद्ध बहुत हाईटेक हो चले हैं। जिसमें रेडी-टू-यूज हथियारों की खास अहमियत है। यह जानते हुए कि किसी सशस्त्र संघर्ष में पिछड़ने के मायने हैं कि शिकस्त को टाला नहीं जा सकेगा।

आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ती दुनिया..!

अर्थव्यवस्था

-सिद्धायनी जैन

मार्च के पहले पखवाड़े में ही अमेरिका के दो प्रमुख बैंकों- सिग्नेचर बैंक और सिलिकान वैली बैंक - के डूबने की खबरों ने दुनिया भर के शेयर बाजारों ने गोता खाना शुरू कर दिया। उधर क्रेडिट सुइस नाम के वित्तीय संस्थान में भी जागी कुछ अनिश्चितताओं ने तो सबको चिंतित कर दिया। यूरोप के कई बैंकों की आर्थिक स्थिरता पर इसका असर पड़ा और इसने उन लोगों में आशंका पैदा कर दी, जिनके वित्तीय हित किसी भी बैंकिंग संस्थान से जुड़े हैं। उल्लेखनीय है कि कई महीने पहले विश्व मुद्रा कोष और कुछ अर्थशास्त्रियों ने आशंका जता दी थी कि 2023 में दुनिया एक बार फिर आर्थिक मंदी झेलने को मजबूर हो सकती है। क्या सचमुच ऐसा होगा दुनिया कुछ समय पहले ही एक वैश्विक महामारी से उबरी है। कुछ ही दिन बीते जब श्रीलंका में जनता सत्ता के खिलाफ सड़कों पर थी, पाकिस्तान में भी हालात काबू में नहीं हैं। ब्रिटेन में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। रूस और यूक्रेन के बीच साल भर पहले शुरू हुए युद्ध में अब दूसरी ताकतें भी कूदती नजर आ रही हैं। खबर है कि अमेरिका, जिसने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है, के कट्टर विरोधी देशों रूस, चीन और ईरान ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। क्या यह किसी बड़े विप्लव का संकेत है

याद कीजिए कि 1930 की महामंदी के पहले भी कुछ ऐसे ही हालात थे। बस, वित्तीय संस्थानों के डूबने, महामारी और युद्ध के माहौल के क्रम में कुछ तब्दीली है। सन 1914 से 1918 के बीच पहला विश्वयुद्ध लड़ा गया था। युद्ध खत्म ही हुआ था कि स्पेनिश फ्लू की महामारी फैल गई, जिसमें करीब पांच करोड़ लोगों की जान चली गई। उसके बाद हालात सुधरे तो आर्थिक संपन्नता के मुक्त उल्लास के दिन आए। 1920 के दशक में अमेरिका में पूंजीवाद का उत्थान हुआ। लोग गांव छोड़ कर शहरों की तरफ जाने लगे। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ गई। हर पांचवें घर के बाहर एक नई कार खड़ी हो गई। दरअसल, बैंकों ने लोगों को खुल कर ऋण बांटे थे।

1920 के दशक में अमेरिका में आई आर्थिक समृद्धि के पीछे एक और कारण था पूंजी बाजार। लोग पैसा लगा कर अपनी राशि को बढ़ते हुए देखने के आदी हो गए। आज भी यह निवेश का एक बड़ा बाजार है। हर आर्थिक वर्ग का आदमी शेयर बाजार में पैसा लगाकर सुनहरे भविष्य के सपने संजोए खड़ा है। अच्छे दिनों के सपने देखना बुरा भी नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब अप्रत्याशित तरीके से शेयर बाजार औंधे मुंह गिर जाता है और कम पूंजी वाले लोग ऐसे भंवर में घिर जाते हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आता। बैंक अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए ब्याज दर बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है, मुद्रा स्फीति लोगों की उम्मीदों को आंखें दिखाने लगती है।

1920 के दशक में अमेरिका में आर्थिक उथल- पुथल मची तो अगस्त 1929 तक पहुंचते-पहुंचते बैंकों पर इतना कर्ज चढ़ गया कि उन्हें चुकाना मुश्किल लगने लगा। बाजार में ऋण का प्रवाह कम हुआ तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम हुई। इससे उत्पादन घटाना पड़ा। बेरोजगारी बढ़ने लगी। महंगाई को तो बढ़ना ही था। हालात कठिन होते देख कर निवेशकों ने इतने शेयर बेच दिए कि पूंजी बाजार ध्वस्त हो गया। यह प्रवृत्ति बढ़ती गई। आर्थिक हालात बिगड़े तो कई कारखाने बंद हुए। नतीजा यह हुआ कि बेराजगारी चरम पर पहुंच गई। उधार लेकर शान की जिंदगी जीने वाले परिवार कर्ज की दलदल में धंस गए। किसानों के पास खड़ी फसल कटवाने के लिए मजदूरी देने के पैसे नहीं थे।

इस तरह एक तरफ अनाज खेतों में नष्ट हो गया, तो दूसरी तरफ 1930 में अकाल पड़ गया। लोग सरकार की तरफ मदद की आस लगाए देखने लगे। मगर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हरबर्ट हूवर लोगों को झूठी दिलासा देते रहे कि यह आर्थिक संकट जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का काम नौकरियां पैदा करना या आर्थिक सहयोग देना नहीं है। लोग उनसे नाराज हो गए और परिणाम यह हुआ कि 1933 में अमेरिका की कमान फ्रेंकलिन रूजवेल्ट को दे दी गई। धीरे-धीरे रूजवेल्ट ने कुछ पहल की और हालात सुधरे। मगर तब तक इस महामंदी का असर ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, जापान और भारत तक फैल चुका था।

1930 की आर्थिक मंदी ने दुनिया को एक नया राजनीतिक तेवर भी दिखाया। मंदी के दौरान लोगों में क्षेत्रीयता बढ़ी। कई देशों में कट्टरपंथी राजनीतिक विचारों को लोगों का समर्थन मिला। यही कारण है कि जर्मनी में उन्हीं दिनों हिटलर का उदय हुआ। 1932 के चुनावों के बाद हिटलर की नाजी पार्टी जर्मनी की संसद में पहुंचने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। जब अलग-अलग समूहों की कट्टरता बढ़ती है, तो उनके हित टकराते हैं। ऐसी स्थितियां अगर समय रहते न संभाली जाएं तो विकट युद्ध का रूप धारण कर लेती हैं। वही परिस्थितियां सन 1941 में दूसरे विश्वयुद्ध का कारण बनीं।

एक बार फिर अमेरिका में महत्तवपूर्ण बैंक डूबे हैं। लोगों को डर है कि कहीं यह वित्तीय संस्थानों के दरकने के सिलसिले की शुरुआत न हो। इसके पहले कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी हैं। जर्मनी, आस्ट्रिया, फ्रांस, हंगरी, इटली और स्पेन जैसे देशों में भी कट्टरवादी राजनीतिक ताकतों ने अपना वर्चस्व बढ़ाया है। मुद्रास्फीति का हाल यह है कि जनवरी 2023 में ही तुर्की की मुद्रास्फीति की दर 55 प्रतिशत से अधिक थी। पिछले अनुभवों को देखते हुए ये स्थितियां आशंकित करती हैं, क्योंकि एक साल की बंदी के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इसका असर महामंदी जैसा हो सकता है। सन 2008 में भी मंदी की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। उस साल वहां की नामी वित्तीय कंपनी लेहमन ब्रदर्स दिवालिया हुई, तो दुनिया भर में उथल-पुथल मच गई थी। उस समय निवेशकों को जितना नुकसान हुआ, वह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर थी

सन 2008 में आई मंदी का असर भारत पर अपेक्षाकृत कम देखने को मिला था, क्योंकि आम भारतीय अब भी अपनी कमाई में से छोटी-छोटी बचत करने का आदी रहा है। आज भी रसोई के किसी कनस्तर में गृहणी द्वारा बचा कर रखा गया धन देखने को मिल सकता है। बच्चों की गुल्लक में, छोटी आवर्ती जमा योजनाओं में हमारी बचत इतराती है। यह अलग बात है कि अब बड़े संकट में यह राशि बहुत छोटी प्रतीत होती है। नौकरीपेशा आदमी आयकर बचाने के लिए राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान बचत पत्र, पीपीएफ जैसी योजनाओं में निवेश करता हैं और कठिन दिनों के लिए अपना आधार तैयार करता है।

विलुप्त जीवों को फिर जीवित करने की पहल

दृष्टिकोण

-मुकुल व्यास

वैज्ञानिक काफी समय से डोडो और ऊनी मैमथ जैसे विलुप्त हो चुके जीवों को फिर से जीवित करने की योजना बना रहे हैं। कोलोसल बायोसाइंसेज नामक एक अमेरिकी कंपनी ने डोडो और अन्य विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की परियोजना के लिए 14 करोड़ डॉलर से अधिक राशि जुटाई है। ध्यान रहे कि डोडो पक्षी मॉरीशस में पाए जाते थे। कबूतर जैसा यह पक्षी उड़ान नहीं भर सकता था। द्वीपों पर पाए जाने वाले कई उड़ान रहित पक्षियों की तरह डोडो बंदरों और बिल्लियों के शिकार बने जिन्हें लोगों के प्रवासन के माध्यम से लाया गया था। यह पक्षी 1600 के मध्य दशक में विलुप्त हो गया। एक बार उम्मीद जगी थी कि क्लोनिंग तकनीक कुछ विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित कर सकती है। साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट (स्थायी तुषार भूमि) में जमे हुए मैमथ पाए जाने के बाद वैज्ञानिक काफी उत्साहित हो गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि उनके जीन बहुत खंडित थे।

हाल के वर्षों में डीएनए को क्रमबद्ध करने में भारी प्रगति हुई है जिसकी वजह से वैज्ञानिक काफी समय पहले विलुप्त हो चुके जीवों का आनुवंशिक कोड स्थापित करने में सक्षम हो गए हैं। तस्मानियाई बाघ, पैसेंजर पिजन (एक तरह का जंगली कबूतर) और ग्रेट औक (उड़ान-रहित पक्षी) एक सदी पहले विलुप्त हो गए थे। इनके जीनों को क्रमबद्ध किया जा चुका है। इसी तरह कुछ हजार साल पहले विलुप्त हो चुके हाथी के रिश्तेदार ऊनी मैमथ के जीनों को भी क्रमबद्ध किया जा चुका है। सबसे बड़ा आश्चर्य उस समय हुआ जब 1997 में एक स्वीडिश वैज्ञानिक ने निएंडरथल मानव के डीएनए का नक्शा बनाने में कामयाबी हासिल की जो 40,000 से अधिक वर्ष पहले विलुप्त हो चुका था। पिछले साल डोडो के आनुवंशिक कोड को

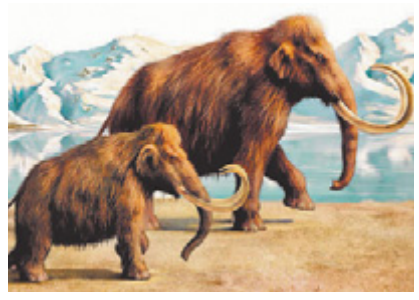

समझने में कामयाबी मिली।जुरासिक पार्क फिल्म दिखाए दृश्यों के सजीव होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि करोड़ों वर्षों पहले मृत हो चुके डायनासोरों के जीवाश्म दुर्लभ हैं और उनकी आनुवंशिक सामग्री बहुत पहले ही बिखर चुकी है। पेड़ों के तनों की गोंद (एम्बर) में कैद में मच्छरों से डायनासोरों के जीन निकालना एक साइंस फिक्शन फिल्म के लिए एक अच्छा प्लॉट बन सकता है लेकिन व्यवहार में यह काम नहीं कर सकता। हालांकि डोडो के मामले में आनुवंशिकी कुछ आसान दिखती है।

विलुप्त प्रजातियों के पुनर्जन्म से पहले वैज्ञानिकों को तीन और छलांगें लगानी होंगी। ये सभी वर्तमान में असंभव हैं लेकिन भविष्य में यह संभव हो सकता है। सबसे पहले वैज्ञानिकों को विलुप्त प्रजाति के जीवित रिश्तेदार की कोशिका के जीनों को संपादित करने में सक्षम होना पड़ेगा ताकि उन्हें विलुप्त प्रजातियों के समान बनाया जा सके। डोडो के लिए निकटतम चचेरा भाई निकोबार कबूतर है और मैमथ भारतीय हाथी का निकटतम रिश्तेदार है। 2012 में जीन संपादन के आविष्कार के बाद विलुप्त जीवों को फिर से जिंदा करने की बात अब साइंस फिक्शन नहीं रह गई है। लेकिन वर्तमान जीन संपादन तकनीक एक कबूतर के जीनोम (एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए का पूरा सेट) से एक डोडो जीनोम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सटीक रूप से काम नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए लाखों तरह के छोटे-मोटे बदलाव की आवश्यकता होती है। फिर भी प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ रही है और एक दशक के भीतर कबूतर कोशिका में डोडो के समस्त जीनों को फिट करना संभव हो सकता है। अगला कदम उस कोशिका को एक पक्षी में बदलना होगा। कुछ साल पहले यह भी असंभव लगता था।

स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टिट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक बत्तख के भ्रूण में मुर्गे की कोशिकाओं को प्रत्यारोपित करने का तरीका खोजा है। एक दिन घरेलू कबूतरों का एक नर और मादा का सेट डोडो के शुक्राणु और डोडो के अंडे पैदा करने में सक्षम हो जाएगा। दोनों मिलकर एक संपूर्ण डोडो को जन्म देंगे। मैमथ को फिर से जीवित करना अधिक कठिन होगा क्योंकि मैमथ भ्रूण को प्रत्यारोपित करने के लिए उपयुक्त गर्भ खोजना होगा क्योंकि भारतीय हाथी बाहरी भ्रूणों को अस्वीकार कर देंगे। कोलोसल कंपनी का कहना है कि वह एक कृत्रिम गर्भ बनाने की योजना बना रही है लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं होगा।

इस प्रक्रिया के अगले कदम के रूप में कुछ स्वस्थ नए नमूनों को पालना होगा। उन्हें प्रजनन के लिए तैयार करना होगा और आनुवंशिक रूप से विविध आबादी उत्पन्न करनी होगी जो जंगल की परिस्थितियों में जीवित रह सके। इस प्रयोग में कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जीन संपादन के दौरान एक छोटी सी गलती होने पर विलुप्त प्रजाति के शुरुआती जानवर भयानक रूप से विकृत हो सकते हैं। विलुप्त जीवों को फिर से जिंदा करने की योजना कई सवाल खड़े करती है। क्या ऐसा किया जा सकता है क्या यह सुरक्षित रहेगा और क्या यह नैतिक है लेकिन जहां तक विलुप्त जीवों को पुनर्जीवित किए जाने के खिलाफ नैतिक आपत्तियों की बात है तो उनमें से कई निराधार निकलीं। वास्तव में हम निश्चिंत हो सकते हैं कि एक विलुप्त प्रजाति अपने साथ नई बीमारियां वापस नहीं लाएगी। हालांकि, परमाफ्रॉस्ट में मिले मैमथ हाथियों के अवशेष अनेक प्रकार के रोगाणुओं को संरक्षित कर सकते हैं। इनसे खतरा हो सकता है लेकिन नवजात जानवर कोई जोखिम उत्पन्न नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जानवर किसी कारण से विलुप्त हो जाते हैं इसलिए बेहतर है कि उन्हें विलुप्त ही रहने दिया जाए। लेकिन इस 'कारण' के पीछे ज्यादातर मनुष्य का लालच रहा है। उसने ग्रेट औक्स पक्षी को तकिए की भराई में बदल दिया। मनुष्य की लापरवाही भी एक बड़ा कारण है। जिन जानवरों ने डोडो को मार डाला, वे लोगों द्वारा ही मॉरीशस लाए गए थे।

जब मैमथ की बात आती है तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि उनके नुकसान ने साइबेरिया की पारिस्थितिकी को बदल दिया। उपजाऊ घास के मैदान देवदार के अनुपजाऊ जंगल में बदल गए। उन घास के मैदानों को फिर से बनाना स्तनपायी और पक्षियों की अन्य प्रजातियों के लिए अच्छी खबर होगी। वैसे मैमथ आज के अफ्रीकी हाथियों की तुलना में अधिक डरावने या खतरनाक नहीं होंगे। फिर भी हमें सावधानी से चलने की जरूरत है। विलुप्त जानवरों को पुनर्जीवित करने की कोशिश जैव प्रौद्योगिकी सख्त नियमों के अधीन होनी चाहिए।

आजकल

लापरवाही का कांचीपुरम् हादसा

कुछ काम-धंधे ऐसे होते हैं, जिनमें हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। इसलिए उनमें सतर्कता और सुरक्षा संबंधी उपायों का गंभीरता से पालन ही सबसे कारगर तरीका माना जाता है। मगर हमारे देश में औद्योगिक सुरक्षा संबंधी नियम-कायदों को किस तरह ताक पर रख कर बहुत सारे कल-कारखाने चल रहे हैं, यह छिपी बात नहीं है। इनकी मनमानियों पर नजर रखने वाले अमले आंखें बंद किए रहते हैं। उनकी आंखें तब खुलती हैं, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। तब कुछ दिन की सतर्कता और नियम-कायदों के पालन में बरती जाने वाली लापरवाहियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दम भरने के साथ फिर से आंखें बंद कर ली जाती हैं।

इसी का नतीजा है कि कल-कारखानों में हादसों और उनमें काम करने वाले मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक पटाखा कारखाने में लगी आग में नौ मजदूरों के मारे जाने और बारह के गंभीर रूप से घायल हो जाने की घटना उसी की एक कड़ी है। इस तथ्य से कोई अनजान नहीं कि पटाखों के निर्माण में अतिज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल होता है, उनके कारखानों में लापरवाही की मामूली चिनगारी भी भयावह रूप ले सकती है। फिर भी ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो जाहिर है कि उनमें जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता। हर घटना के बाद यह सवाल उठता है कि आखिर सरकारें पटाखा बनाने वाले कारखानों में मजदूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में कैसे विफल हैं। दक्षिण भारत में पटाखे का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है। इनमें ज्यादातर काम मजदूर हाथ से करते हैं। पटाखे बनाने से लेकर उनके भंडारण तक। इस काम के लिए उन्होंने कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया होता है। इसी का लाभ अक्सर कारखाना मालिक उठाते हैं। हालांकि पटाखे बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उससे संबंधित नियम-कायदे बहुत सख्त हैं। फिर भी कारखाना मालिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने से बाज नहीं आते। फिर जो कारखाने चोरी-छिपे चलाए जाते हैं, उनसे भला नियम-कायदों के पालन की कितनी उम्मीद की जा सकती है। औद्योगिक हादसों पर लगाम न लग पाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उनमें मारे जाने वाले लोगों के लिए मुआवजे का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

जन-भागीदारी से ही जल संकट का समाधान...

मुद्दा

-दीपक कुमार शर्मा

ऋग्वेद में वर्णित है कि जल आनंद का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है। कल्याणकारी है। पवित्र करने वाला है और मां की तरह पोषक तथा जीवनदाता है। दरअसल, जल इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं। साथ ही पीने योग्य जल धरती पर अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में दुनियाभर में पानी व्यर्थ न बहाने व साथ ही बचाने की कोशिशें जारी हैं। जन जागरूकता अभियान सरकारों व अन्य संस्थाओं के स्तर पर जारी है। इसी के तहत जल बचत, संचय व पुन: उपयोग करने जैसे लक्ष्य तय किये जाते हैं। इसी क्रम में हम जल दिवस मनाते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जल संरक्षण का संदेश बार-बार देना पड़ता है। देखा जाये तो जीडीपी, रोजगार सब व्यर्थ हैं, अगर पानी नहीं होगा।

हम पानी पीते तो हैं, मगर पानी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। हालांकि जल संरक्षण एक नागरिक के तौर पर भी हमारा दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (छ) के मुताबिक, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है- वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।

जीवन की मूलभूत आवश्यकता पानी है। मानव विकास के लिए पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। देश के लिए पानी खासी अहमियत रखता है। दुनिया की कुल आबादी में से लगभग 18 प्रतिशत लोग और 15 प्रतिशत मवेशी भारत में रहते हैं। लेकिन दुनिया की कुल जमीन में से हमारे पास मात्र 2 प्रतिशत भूमि और मीठे पानी के 4 प्रतिशत संसाधन हैं। अनुमानों के अनुसार, साल 1951 में मीठे पानी की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 5177 घन मीटर थी जो 2019 में लगभग 1368 घन मीटर रह गयी, जो 2025 में घटकर संभवत: 1293 घन मीटर रह जाएगी। यदि यह गिरावट जारी रही तो वर्ष 2050 में मीठे पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटकर 1140 घन मीटर ही रह जाएगी जो कि चिंता का विषय है।

देश की आबादी बढ़ने से पानी की खपत भी बढ़ रही है। पानी भू-जल के रूप में 28 प्रतिशत ही बचा है, जबकि पीने का पानी, खेती,

उद्योग, सब में भू-जल का उपयोग कर रहे हैं। असल में जब तक निर्वहन और पुनर्भरण में संतुलन नहीं होगा, तब तक देश पानीदार नहीं बन सकता। भारत सरकार जल संरक्षण को लेकर प्रयास कर रही है। चाहे जल जीवन मिशन हो, अमृत सरोवर योजना हो या अटल भू-जल योजना हो। पंद्रह अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर घर को नल से जल देना है। उस समय देश में सिर्फ 16.66 प्रतिशत घरों को नल से जल मिल रहा था।

इसकी तुलना में अब 59.10 प्रतिशत घरों को नल से जल मिल रहा है। पानी के संचय को लेकर अमृत सरोवर योजना के माध्यम से 15 अगस्त, 2023 तक देश भर के प्रत्येक जिले में 75-75 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। नए तालाब खोदे जाएंगे और पुराने पुनर्जीवित किये जायेंगे। इसी दिशा में एक अन्य कदम अटल भू-जल योजना है। इसके तहत देश के 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भू-जल प्रबंधन में सुधार करना है।

यहां सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सरकार के प्रयासों से जल संरक्षण हो पाएगा। सच तो यह है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जल संरक्षण नहीं होगा। पानी हम सबकी साझी संपत्ति है। पानी के ऊपर सबका समान अधिकार है तो हमें जल संरक्षण की दिशा में मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को जल संकट का सामना न करना पड़े। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 में कई शहर ऐसे होंगे जहां जमीन के नीचे का पानी खत्म हो चुका होगा। देश की 6 प्रतिशत जीडीपी दर पानी न होने के कारण प्रभावित होगी। अब भी देश के महानगर चेन्नई में 2000 फुट गहरे तक पानी नहीं है।

पानी को लेकर हमारी मन:स्थिति अलग-अलग है। कोई भी इंसान बोतलबंद पानी का दुरुपयोग नहीं करता है। लेकिन नल के जल की हम बेपरवाह होकर बर्बादी करते हैं क्योंकि हमें लगता है पानी मुफ्त में मिल रहा है। जबकि सच यह है कि सरकार हमें हमारे ही पैसों से पानी उपलब्ध करवाती है। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह पानी बचाकर व संचित कर सरकारी पैसे का सदुपयोग करे। नल से जल का सही इस्तेमाल करे। ऐसे में सभी स्तरों पर जल संरक्षण की 5 आर रणनीति कारगर साबित हो सकती है।